भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5749
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जर्मन मंत्रिमंडल द्वारा 'फोकस ऑन इंडिया' दस्तावेज को स्वीकार करना

5749. **डॉ. सी. एम. रमेशः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जर्मन मंत्रिमंडल द्वारा 'फोकस ऑन इंडिया' दस्तावेज को स्वीकार कर लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दस्तावेज से भारत को कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) क्या गत वर्ष अक्तूबर में दोनों देशों के बीच अंतर-सरकारी परामर्श हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) जी, हां। जर्मन मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर 2024 को 'फोकस ऑन इंडिया' दस्तावेज़ को अंगीकृत किया है। इस दस्तावेज में भारत के साथ जर्मनी की रणनीतिक सहभागिता को घनिष्ठ बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा दी गई है, जिसमें बदलते वैश्विक परिदृश्य में स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक लोकतांत्रिक सहभागी के रूप में भारत की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसमें सुरक्षा सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी, आर्थिक, व्यापार और कृषि संबंधी सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक संपर्क, बहुपक्षीय सहयोग, संसदीय संपर्क सहित समाज में आदान-प्रदान को बढ़ाना, कुशल आव्रजन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के समग्र संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है।

(ख) इस दस्तावेज में जर्मनी की संघीय गणराज्य सरकार के भारत के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के आशय पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत को जर्मनी के पसंदीदा सहभागी के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों पक्ष 2025 में रणनीतिक सहभागिता की 25$^{वीं}$ वर्षगांठ मना रहे हैं और इन्होंने व्यापार एवं निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग में बढ़ोतरी की है। वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत-जर्मनी व्यापार 33.5

बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। जर्मनी में पढ़ने वाले लगभग 50 हजार भारतीय छात्र, जिनकी संख्या पिछले 5 वर्षों में दोगुनी हो गई है, अब जर्मनी में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं।

(ग) और (घ) जी हां। 7वां अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की यात्रा के दौरान आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री और चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की अध्यक्षता में आईजीसी पूर्ण अधिवेशन से पहले विदेश नीति और सुरक्षा; अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य; हरित एवं सतत विकास साझेदारी, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां और नवाचार; गतिशीलता और लोगों के बीच आपसी संबंध; और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी मंत्रिस्तरीय बैठकें हुईं। आईजीसी की पूर्ण बैठक और मंत्रिस्तरीय बैठकों में हमारी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और इसे और घनिष्ठ एवं विविधतापूर्ण बनाने के लिए आगे के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, त्रिकोणीय विकास सहयोग, कौशल, शिक्षा और अनुसंधान, शहरी गतिशीलता, स्टार्टअप, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में ठोस परिणाम सामने आए। 7वीं आईजीसी के परिणामों की संपूर्ण सूची संलग्न है।

*****

अनुबंध- I

7वें भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के परिणामों की सूची

[25 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली]

I. परिणामी दस्तावेज

क्र.सं.	दस्तावेज	क्षेत्र
1.	नवाचार और प्रौद्योगिकी संबंधी रोडमैप	नई एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ
2.	ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप दस्तावेज़ का आरंभ	हरित ऊर्जा
3.	आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए संधि (एमएलएटी)	सुरक्षा
4.	वर्गीकृत सूचना के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण के लिए करार (प्रारंभिक)	सुरक्षा
5.	हरित शहरी आवाजाही सहभागिता-II के लिए जेडीआई	शहरी आवाजाही
6.	आईजीएसटीसी के तहत उन्नत सामग्री के लिए 2+2 कॉल संबंधी जेडीआई	विज्ञान प्रौद्योगिकी
7.	मैक्स-प्लैंक-गेसेलशाफ्ट ईवी (एमपीजी) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज (आईसीटीएस), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के बीच समझौता ज्ञापन	विज्ञान प्रौद्योगिकी
8.	मैक्स-प्लैंक-गेसेलशाफ्ट ईवी (एमपीजी) और 12 पीटी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (एनसीबीएस), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के बीच समझौता ज्ञापन	विज्ञान प्रौद्योगिकी
9.	डीएसटी और जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) के बीच नवाचार और इनक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम संबंधी जेडीआई	स्टार्ट अप्स
10.	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) और जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र (जीएफजेड) के बीच समझौता ज्ञापन	पर्यावरण एवं विज्ञान
11.	राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) और अल्फ्रेड-वेगेनर इंस्टीट्यूट हेल्महोल्ज़ ज़ेंट्रम फ़्यूर पोलर एंड मीरेसफ़ोर्सचंग (एडब्ल्यूआई) के बीच ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान संबंधी समझौता ज्ञापन	पर्यावरण एवं विज्ञान
12.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (सीएसआईआर - आईजीआईबी) और लीपज़िग विश्वविद्यालय के बीच संक्रामक रोग जीनोमिक्स में सहयोगी अनुसंधान और विकास के लिए जेडीआई	स्वास्थ्य
13.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद – जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (सीएसआईआर – आईजीआईबी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), लीपजिग विश्वविद्यालय और भारत में उद्योग भागीदारों के बीच नैदानिक उद्देश्यों के लिए मोबाइल सूटकेस लैब संबंधी साझेदारी के लिए जेडीआई	स्वास्थ्य

14.	भारत-जर्मनी प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईजीएमटीपी) के लिए जेडीआई	अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य
15.	कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	कौशल विकास
16.	श्रम और रोजगार के संयुक्त आशय घोषणा	श्रम एवं रोजगार
17.	आईआईटी खड़गपुर और जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) के बीच संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम 'जर्मन इंडिया एकेडमिक नेटवर्क फॉर टुमॉरो (जीआईएएनटी)' के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम निवेश (जेडीआई) के लिए हस्ताक्षर	शिक्षा और अनुसंधान
18.	आईआईटी मद्रास और टीयू ड्रेसडेन के बीच 'ट्रांसकैम्पस' के नाम से गहन साझेदारी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन	शिक्षा और अनुसंधान

II. प्रमुख घोषणाएं

19.	आईएफसी-आईओआर में एक जर्मन संपर्क अधिकारी की नियुक्ति
20.	यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत के पर्यवेक्षक दर्जे के लिए जर्मनी का समर्थन
21.	हिंद- प्रशांत महासागर संबंधी पहल (आईपीओआई) के तहत जर्मन परियोजनाएं और 20 मिलियन यूरो की वित्त पोषण प्रतिबद्धता
22.	भारत और जर्मनी के विदेश कार्यालयों के बीच क्षेत्रीय परामर्श स्थापित करना (अफ्रीका, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका)
23.	त्रिकोणीय विकास सहयोग (टीडीसी) ढांचे के अंतर्गत मेडागास्कर और इथियोपिया में श्री अन्न से संबंधित पायलट परियोजनाएं तथा कैमरून, घाना और मलावी में पूर्ण पैमाने की परियोजनाएं
24.	जीएसडीपी डैशबोर्ड का शुभारंभ
25.	भारत और जर्मनी के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण समूह की स्थापना

III. आयोजन

26.	जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया-प्रशांत सम्मेलन (एपीके 2024) का आयोजन
27.	एपीके 2024 के अवसर पर रक्षा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन
28.	जर्मन नौसेना के जहाजों की हिंद-प्रशांत तैनाती: भारतीय और जर्मन नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और गोवा में जर्मन जहाजों का बंदरगाह पर लंगर डालना

*****